



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2001/पौष 22, 1922

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2001/PAUSA 22, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2001

सं. 67/1/2000-डीजीएडी.— मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के नियम 5(1)के अनुसार जापान, कोरिया गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य और बंगलादेश (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से लैड एसिड बैटरियों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए एक याचिका दायर की है।

2. घरेलू उद्योग: यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्त्ताओं ने बताया है कि भारत में संगठित क्षेत्र में इस उत्पाद के ऐसे पांच अन्य उत्पादक भी हैं जो संबद्ध देशों से लैड एसिड बैटरियों का यदा-कदा आयात कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में भी अनेक लघु उत्पादक हैं।

यद्यपि अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड ने संबद्ध देशों से लैड एसिड बैटरियों के कुछेक माडलों का आयात किया है जिनका उनके द्वारा स्वयं विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, तथापि आयात की मात्रा और मूल्य उनके द्वारा संबद्ध वस्तुओं के वार्षिक उत्पादन और बिक्री की तुलना में काफी अधिक रहा है। इसलिए, प्राधिकारी ने मैसर्स अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों को नजरअन्दाज करने का निर्णय लिया है और उसे याचिका दायर करने के उद्देश्य से घरेलू

उद्योग की परिभाषा में शामिल किया है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ताओं का हिस्सा घरेलू उद्योग के उत्पादन का आधा प्रतिशत से अधिक बनता है और वे घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में है।

3. विचाराधीन उत्पाद: विचाराधीन उत्पाद "लैड एसिड बैट्रियां" हैं। ये सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के उपशीर्ष संख्या 8507 के अंतर्गत आती हैं। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लैड एसिड बैट्रियों की निकासी उपशीर्ष 8504 एवं 8506 के तहत भी की गई है। बैट्रियां विद्युत/धारा की संचायक होती हैं, जो एक समयावधि के बाद समाप्त हो जाती हैं। इनका उपयोग वाहनों में तथा यू पी एस अनुप्रयोग के लिए बैकअप पावर नियंत्रण कक्ष, विद्युत घर, दूर-संचार इत्यादि जैसे विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि लैड एसिड बैट्रियों के मामलों के आंकड़े यूनिटों की संख्या में रुप में संगृहीत किए गए हैं। लेकिन इसकी मात्रा को यूनिटों की संख्या के रुप में निरूपित करना भ्रामक हो सकता है। क्योंकि भिन्न-भिन्न माडलों की भिन्न-भिन्न विद्युत क्षमता तथा मूल्य होते हैं। उत्पाद को यूनिट तथा मूल्य के रुप में निरूपित करने के अलावा, यह लैड तत्व के रुप में उत्पाद के संबंध में सूचना हासिल करने में लाभकारी होगा क्योंकि बैटरी की विद्युत तथा लैड तत्व के बीच सीधा सहसंबंध होता है, जिसे मूल्य अथवा कीमत के रुप में भी प्रदर्शित किया जाता है। बैट्रियों में लैड तत्व तथा इससे संबंधित लागत एवं कीमत के बीच सीधा संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए विभिन्न मापदण्डों की तुलना तथा गणना के उद्देश्य से यह उचित होगा कि उत्पाद की मात्रा, मूल्य तथा लैड तत्व का आकलन किया जाए।

4. शामिल देश: याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं और इन देशों के खिलाफ जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

5. समान वस्तु: याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबंध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के "समान वस्तु" है। इसलिए जांच के प्रयोजनार्थ

याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित लैड एसिड बैटरियों (जिन्हें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

6. सामान्य मूल्य: याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की आकलित लागत के आधार पर तथा संबद्ध वस्तु के कुछ संबद्ध देशों में घरेलू कीमत के बारे में साक्ष्य के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के बारे में प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

7. निर्यात कीमत: निर्यात कीमत का दावा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता से प्राप्त तथा द्वितीयक स्रोतों से संकलित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निबल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए हैंडलिंग प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग इत्यादि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत तथा दावा किए गए समायोजनों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

8. पाटन मार्जिन: इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निबल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति और कारणात्मक संबंध: याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप उनके बाजार हिस्से में कमी, कीमत में कटौती तथा घरेलू उद्योग को प्राप्त न्य ठेकों को गँवाए जाने के रूप में हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग को पहले से

हुई वास्तविक क्षति के अलावा, कथित रूप से पाटित आयातों से और अधिक क्षति होने का खतरा भी बना हुआ है, जिससे उन्हें पहले से ही हो रही वास्तविक क्षति में और वृद्धि हो जाएगी ।

10. पाटनरोधी जांच की शुरुआत: उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2000 से 30 सितम्बर, 2000 (9 महीने) तक की है ।

12. सूचना प्रस्तुत करना: संबंधित समझे जाने वाले निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करें । वर्तमान जांच में शामिल होने की इच्छुक अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दिए गए पते पर लिख सकती है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय),
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110011

13. समय सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित समस्त सूचना लिखित रूप में भेजी जाए, जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है ।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल.बी. सत्यश्रुति, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2001

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning import of lead acid batteries originating in or exported from Japan, Korea, China and Bangladesh

No. 67/1/2000-DGAD.— Exide Industries Limited and M/s. Amara Raja Batteries Limited have filed a petition for initiation of anti dumping investigation concerning the import of lead acid batteries from Japan, Republic of Korea, People's Republic of China and Bangladesh (hereinafter referred to as subject countries) in accordance with Rule 5(1) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.

2. **Domestic Industry:** The petition has been filed by M/s. Exide Industries Limited and M/s. Amara Raja Batteries Limited on behalf of the domestic industry. The petitioners have averred that there are five more producers of the product in the organized sector in India who incidentally are also importing lead acid batteries from subject countries. Also, there are a number of small producers in the un-organised sector.

Though M/s. Amara Raja Batteries Ltd., have made import of certain models of lead acid batteries from the subject countries which they themselves are not manufacturing, the volume and value of import is quite insignificant as compared with the annual production and sales of the subject goods by them. Therefore, the Authority has decided to ignore the imports made by M/s. Amara Raja Batteries Ltd., and include them in the definition of domestic industry for the purpose of filing the petition. On the basis of the evidence available, the petitioners account for more than fifty percent of the production of domestic industry and have the standing to file the petition on behalf of domestic industry.

3. **Product under consideration:** The product under consideration is "lead acid batteries". This falls within Chapter 85 of the Custom Tariff Act under the sub-heading 8507. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation. It has been stated by the domestic industry that lead acid batteries have also been cleared by the Custom Authorities under sub-heading 8504 and 8506 as well. Batteries are accumulator of current/power which is discharged over a period of time.

They are used in vehicles and also for various industrial uses, such as for back up power for UPS applications, control rooms, power stations, telecommunications etc.

It has been stated by the domestic industry that the statistics in the case of lead acid batteries are compiled in terms of number of units. But denoting the volume in terms of number of units may be misleading because different models have different power capacity and value. Apart from denoting the product in terms of units and value, it will be useful to have the information on the product in terms of lead content as there is a direct correlation between power and lead content of the battery which also gets reflected in terms of value or price. The direct correlation between the lead content in the battery and its associated costs and prices is also quite significant. It will, therefore, be meaningful to assess the volume, value as well as lead content of the product for the purpose of calculation and comparison of various parameters.

4. **Countries involved:** The petitioners have provided evidence of dumping of the product under consideration from subject countries and have requested for initiation of investigation against these countries.

5. **Like Article:** The petitioners have claimed that the goods produced by them are 'like article' to the goods originating in or exported from the subject countries. Therefore, for the purpose of investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of lead acid batteries (hereinafter referred to as subject goods) imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. **Normal Value.** The petitioners have claimed normal value based on the constructed cost of production as well as on the basis of evidence regarding domestic prices in some of the subject countries of the subject goods. Sufficient *prima facie* evidence has been presented to the Designated Authority with regard to the normal value of subject goods in subject countries.

7. **Export Price:** The export price has been claimed on the basis of the data obtained from Director General Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta and compiled from secondary sources. Price adjustments have been claimed on account of landing charges, ocean freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price. There is sufficient evidence of export price and the adjustments claimed for the subject goods from subject countries.

8. **Dumping Margin:** There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating *prima facie* that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

9. **Injury and Causal Link:** The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the allegedly dumped imports in the form of fall in their market share, price undercutting and lost contracts for the domestic industry. In addition to the material injury already inflicted on the domestic industry, the allegedly

dumped imports are also threatening to cause more damage which will intensify the material injury already being suffered by them.

10. **Initiation of Anti Dumping Investigation:** The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. The period of investigation for the purpose of present investigations is 1st January 2000 to 30th September 2000 (9 months).

12. **Submission of Information:** The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan
New Delhi-110011

13. **Time Limit:** All information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra

14. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

